रजिस्टर्ड नं 0 एल 0-33/एस 0 एम 0/13-14/96.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 27 मार्च, 1997/6 चैत्र, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

ग्रधिसूचना

शिमला-4, 27 मार्च, 1997

सं 0 बिधायन/बजट-97-98/1-8/97-वि0स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संच।लन नियमावली, 1973 के नियम, 135 के श्रन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश बिनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1997

916-राजपत्र/97-27-3-97---1,249.

(1021)

मृत्य: 1 रुपया।

(1997 का विधेयक संख्यांक 8) जो दिनांक 27 मार्च, 1997 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपल में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

ग्रजम भण्डारी, संज़िव।

1997 का विधेयक संख्यांक 8

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1997

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के ग्रड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह श्रधिनियमित हो:-

- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) संक्षिप्त नाम । ग्रधिनियम, 1997 है।
- 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से म्रनधिक धनराशियां, जिनका योग 30,88,98,64,000 रुपये (तीस म्ररब, श्रठासी करोड़, अठानवें लाख, चौंसठहजार रुपये) है, संदत्त ग्रौर उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 1997-98 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाग्रों श्रीर निधि में से प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों के सदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा । वित्तीय वर्ष

1997-98 के लिए 30,88,98, 64,000 रुपये राशि जारी करना।

हिमाचल

प्रदेश राज्य

की संचित

 इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त विनियोग । श्रौर उपयोजित करने के लिए प्राधिकृत^{्र}धनराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में श्रभिन्यक्त सेवाभ्रों भीर प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा ।

अनुसूची (धारा 2 श्रौर 3 देखें)

(धारा 2 ग्रीर 3 देखें)						
1	2		3			
मांग संख्या	सेवाएं ग्रीर प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से श्रनधिक			
. લહ્યા			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़	
			रुपये	रुपये	रुपये	
1	विधान सभा ग्रौर निर्वाचन	(राजस्व)	4,34,59,000	9,12,000	4,43,71,000	
2	राज्यपाल भ्रौर मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	2,94,59,000	78,23,000	3,72,82,000	
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	10,82,31,000	2,87,05,000	13,69,36,000	
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	1,74,02,81,000	1,25,20,000	1,75,28,01,000	
		(पूंजी)	25,00,000		25,00,000	
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	59,42,98,000		59,42,98,000 4	
		े (पूंजी)	13,90,000		13,90,000	
6	ग्राबकारी ग्रीर कराधान	(राजस्व)	12,72,11,000		12,72,11,000	
7	पुलिस ग्रीर सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	1,01,47,84,000		1,01,47,84,000	
8	र्शिक्षा, खेलें तथा कला ग्रौर	(राजस्व)	3,67,29,09,000		3,67,29,09,000	
	संस्कृति	े (पूंजी)	5,94,02,000		5,94,02,000	
9	चिकित्सा ग्रौर परिवार कल्याण		1,40,83,28,000		1,40,83,28,000	
		े (पूंजी)	8,91,90,000		8,91,90,000	
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	99,49,32,000		99,49,32,000	
}		े (पूंजी)	10,28,45,000		10,28,45,000	
11	कृषि	(राजस्व)	70,73,72,000		70,73,72,000	
		े (पूंजी)	14,89,35,000		14.89.35.000	
12	सिंचाई ग्रौर बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	47,60,04,000		47,60,04,000	
}		े (पूंजी)	16,57,99,000		16,57,99,000	
13	भूमि ग्रौर जल संरक्षण	(राजस्व)	14,68,64,000	4,00,000	14,72,64,000	
		े (पूंजी)	4,00,000		4,00,000	
14	पशुपालन ग्रौर दुग्ध विकास	(राजस्व)	29,76,61,000		29,76,61,000	
1	3	े (पूंजी)	1,47,02,000		1,47,02,000	
15	मत्स्य	(राजस्व)	2,94,26,000		2,94,26,000	
		े (पूंजी)	1,08,42,000		1,08,42,000	
16	वन ग्रौर वन्य जीवन	(राजस्व)	92,94,58,000		92,94,58,000	
1		े (पूंजी)	1,31,15,000		1,31,15,000	
17	सड़कें ग्रौर पूल	(राजस्व)	1,07,61,90,000		1,07,61,90,000	
	•	(पूंजी)	71,80,68,000		71,80,68,000	
18	ग्रापूर्ति, उद्योग ग्रौर खनिज	(राजस्व)	35,78,71,000		35,78,71,000	
		(पूंजी)	1,42,80,000		1,42,80,000	
19	सामाजिक सुरक्षा ग्रौर कल्याण	(राजस्व)	51,47,13,000		51,47,13,000	
	(पोषाहार सहित)	(पूंजी)	2,31,22,000		2,31,22,000	
1	(18	_, _ , _ , _ , _ , _ 0		2,02,22,000	

San Co

63

1	2		er for the second	3	
			रुपये	रुपये	हपये जड़
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व) (पूंजी)	70,75,67,000 9,00,000		70,75,67,000 9,00,000
21	सहकारिता	(राजस्व) (पूंजी)	10,0 9,4 4,000 7,18,28,000		10,09,44,000 7,18,28,000
22	खाद्य ग्रौर भाण्डागारण	(राजस्व) (पूंजी)	11,33,98,000 28,31,04,000		11,33,98,000 28,31,04,000
23	जल ग्रौर विद्युत विकास	(राजस्व) (पूंजी)	83,00,01,000 98,65,58,000		83,00,01,000 98,65,58,000
24	लेखन सामग्री ग्रौर मुद्रण	(राजस्व) . (पूंजी)	7,82,12,000 18,00,000		7,82,12,000 18,00,000
25	सड़क, जल परिवहन ग्रौर नागर विमानन	(राजस्व) (पूंजी)	25,79,66,000		25,79,66,000 13,62,65,000
26	पर्यटन ग्रौर ग्रातिथ्य संगठन	(राजस्व) (पूंजी)	4,78,75,000		4,78,75,000 4,50,00,000
27	श्रम ग्रौर रोजगार	(राजस्व) (पूंजी)	10,40,84,000 98,00,000		10,40,84,000 : \$\mathbb{\text{\ti}\text{\texi{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texit{\texit{\texi{\texi{\texi\}\\ \\ \\\\\\\\\\\\\ti}\\\\\\\\\\\\\\\
28	जलापूर्ति, सफाई, ग्रावास ग्रौर नगर विकास	(राजस्व) (पूंजी)	1,32,64,93,000 72,46,05,000		1,32,64,93,000 72,46,05,000
29	वित्त वित्त	(राजस्व) (पूंजी)	1,92,70,00,000	4,18,98,38,000 1,42,48,81,000	6,11,68,38,000 1,42,48,81,000
30	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	। (पूंजी)	22,46,50,000		22,46,50,000
31	जन-जातीय विकास	(राजस्व) (पूजी)	1,12,33,73,000 48,93,21,000		1,12,33,73,000 48,93,21,000
1	कुल जोड़		25,22,47,85,000	5,66,50,79,000	30,88,98,64,000
		(राजस्व)	20,88,63,64,000	4,24,01,98,000	25,12,65,62,000
		(पूंजी)	4,33,84,21,000	1,42,48,81,000	5,76,33,02,000
-0-4					

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए हिमाचल अदेश सरकार के अनुमानित व्यमों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्यमों और विधान सभा द्वारा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए प्ररास्थापित है।

वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ।

शिमला, 27 सार्च, 1997.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाईल संख्या वित्त-ए-सी(1)-2/97]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1997 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात, भारत के संविधान के ग्रन्चिंद 207 के ग्रधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने ग्रीर उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 1997.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1997

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 1997-98.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

- 1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1997.
- 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to a sum of Rs. 30,88,98,64,000 (Thirty hundred and eighty eight crores, ninety eight lakhs and sixty four thousands rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1997-98 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the Schedule.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropria-

Short title.

Issue of a

sum of Rs.

64,000 out

of the Con-

the State of

Pradesh for the financial year 1997-98.

Himachal

30,88,98,

solidated Fund of

20

21

22

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1	2	3				
De-			Sums not exceeding			
mand No.	Services and purpo	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Conso- lidated Fund	Total		
1 2	Vidhan Sabha and Election Governor and Council of	(Revenue)	Rs. 4,34,59,000	Rs. 9,12,000	Rs. 4,43,71,000	
	Ministers	(Revenue)	2,94,59,000	78,23,000	3,72,82,000	
3	Administration of Justice	(Revenue)	10,82,31,000	2,87,05,000	13,69,36,000	
4	General Administration	(Revenue)	1,74,02,81,000	1,25,20,000	1,75,28,01,000	
		(Capital)	25,00,000		25,00,000	
5	Land Revenue	(Revenue)	59,42,98,000		59,42,98,000	
		(Capital)	13,90,000	_	13,90,000	
6	Excise and Taxation	(Revenue)	12,72,11,000		12,72,11,000	
7	Police and Allied Organisation	is (Revenue)	1,01,47,84,000		1,01,47,84,000	
8	Education, Sports, Arts and		3,67,29,09,000		3,67,29,09,000	
	Culture	(Capital)	5,94,02,000	~	5,94,02,000	
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	1,40,83,28,000		1,40,83,28,000	
		(Capital)	8,91,90,000		8,91,90,000	
10	Public Works	(Revenue)	99,49,32,000		99,49,32,000	
		(Capital)	10,28,45,000		10,28,45,000	
11	Agriculture	(Revenue)	70,73,72,000		70,73,72,000	
1		(Capital)	14,89,35,000	-	14,89,35,000	
12	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	47,60,04,000	-]	47,60,04,000	
}		(Capital)	16,57,99,000	~	16,57,99,000	
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	14,68,64,000	4,00,000	14,72,64,000	
		(Capital).	4,00,000		4,00,000	
	Animal Husbandry and Dairy	(Revenue)	29,76,61,000		29,76,61,000	
1	Development	(Capital)	1 47 02 000		1 47 02 000	

1,08,42,000 16 Forest and Wild Life 92,94,58,000 (Revenue) 92,94,58,000 74 1,31,15,000 (Capital) 1,31,15,000 Roads and Bridges 17 (Revenue) 1,07,61,90,000 71,80,68,000 (Capital)

Supplies, Industries and (Revenue) 35,78,71,000 Minerals (Capital) 1,42,80,000 1,42,80,000

Development (Capital) 1,47,02,000 1,47,02,000 15 Fisheries (Revenue) **2,94,26,000** 2,94,26,000 1,08,42,000 (Capital)

18 19 Social Security and Welfare 51,47,13,000 (Revenue) 51,47,13,000

(Capital)

1,07,61,90,000 71,80,68,000 35,78,71,000

(Including Nutrition) 2,31,22,000 (Capital) 2,31,22,000 70,75,67,000 Rural Development (Revenue) 70,75,67,000 9,00,000 (Capital) 9,00,000

28,31,04,000

28,31,04,000

Co-operation (Revenue) 10,09,44,000 10,09,44,000 7,18,28,000 (Capital) 7,18,28,000 Food and Warehousing (Revenue) 11,33,98,000 11,33,98,000

	-				
1	2			3	•
			Rs.	Rs.	Rs.
23	Water and Power Develop-	(Revenue)	83,00,01,000		83,00,01,000
1	ment	(Capital)	98,65,58,000	- .	98,65,58,000
24	Stationery and Printing	(Revenue)	7,82,12,000		7,82,12,000
J		(Capital)	18,00,000	;	18,00,000
25	Road, Water Transport and	(Revenue)	25,79,66,000	:	25,79,66,000
*	Civil Aviation	(Capital)	13,62,65,000	i	13,62,65,000
26	Tourism and Hospitality	(Revenue)	4,78,75,000		4,78,75,000
	Organisation	(Capital)	4,50,00,000		4,50,00,000
27	Labour and Employment	(Revenue)	10,40,84,000		10,40,84,000
		(Capital)	98,00,000	- ,	98,00,000
28	Water Supply, Sanitation,	(Revenue)	1,32,64,93,000	•	1,32,64,93,000
	Housing and Urban Developmen	it (Capital)			72,46,05,000
29	Finance	(Revenue)	1,92,70,00,000	4,18,98,38,000	6,11,68,38,000
	1.	(Capital)	-	1,42,48,81,000	1,42,48,81,000
30	Loans to Government Servants	(Capital)	22,46,50,000	_	22,46,50,000
31	Tribal Development	(Revenue)	1,12,33,73,000	_	1,12,33,73,000
		(Capital)		_	48,93,21,000
	Grand To	tal	25,22,47,85,000	5,66,50,79,000	30,88,98,64,000
	(Reven	ue)	20,88,63,64,000	4,24,01,98,000	25,12,65,62,000
٠	(Capit	al)	4,33,84,21,000	1,42,48,81,000	5,76,33,02,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 of the Constitution of India, to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year § 1997-98.

VIRBHADRA SINGH, Chief Minister.

SHIMLA, The 27th March, 1997.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin.-A. C. (1)-2/97]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1997, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.